दैनिक जागरण

शनिवार, 6 फरवरी, 2016 : माघ कृष्ण 13, वि. 2072

जो व्यक्ति अशिक्षित है, वह गरीब है

सरकारी बंगलों का मोह

यह अच्छा-बहुत अच्छा हुआ कि बड़े बंगले में रहने पर आमादा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत भी नहीं मिली और उलटे फटकार भी सुननी पड़ी। संप्रग सरकार में चौधरी को मंत्री होने के नाते बड़ा बंगला मिला था। कायदे से उन्हें लोकसभा चुनाव के दो-चार माह बाद ही वह बंगला खाली कर सांसदों वाले बंगले में चले जाना चाहिए था, लेकिन वह 20 माह तक उस पर डटे रहे और अभी भी डटे रहना चाह रहे थे। इन 20 महीनों में संपदा निदेशालय ने उनसे कई बार मंत्रियों वाला बंगला खाली करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन वह अनसुनी करते रहे। जब उन्हें जबरन निकालने की कार्यवाही शुरू की गई तो वह उच्च न्यायालय चले गए। वहां से उन्हें राहत नहीं मिली तो पता नहीं कैसे वह इस नतीजे पर पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय देने के नाम पर बड़े बंगले में रहने की मोहलत दे देगा? सुप्रीम कोर्ट ने उनका मुगालता दूर करते हुए उन्हें खरी-खोटी तो सुनाई ही, उनसे यह भी पूछा कि वह बंगला खाली करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की याचिकाएं सुननी ही नहीं चाहिए। इस तरह की याचिकाओं को सुनने का मतलब है इसी किस्म की अन्य याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट तक आने देना। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के नाम ऐसी याचिकाएं भी पहुंचें जिनका उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण मामले को लंबा खींचना और बेजा लाभ उठाना होता है। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर अधीर रंजन चौधरी का अड़ियल रवैया पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी नेता ने बड़े बंगले में बने रहने की जिद पकड़ी हो और उसके लिए तरह-तरह के कुतर्क दिए हों।

यह लगातार देखने में आ रहा है कि नेतागण सांसद या मंत्री होने के नाते मिले आवास को छोड़ने के लिए मुश्किल से ही तैयार होते हैं। कभी वे यह तर्क देते हैं कि उन्हें जो वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें सुविधाओं की कमी है और कभी बीमारी अथवा परिजनों की शादी-ब्याह की आड़ लेकर बैठ जाते हैं। कई बार तो सांसद न रहने के बावजूद कुछ नेता महीनों सरकारी आवास पर कब्जा जमाए रखते हैं। गौर करें यही वे लोग हैं जो आम जनता को नैतिकता का उपदेश देते हैं। यह शर्मनाक है कि लोकसभा चुनाव के 20 माह बाद भी कुछ नेता अपने पुराने बंगलों में जमे हुए हैं। इससे भी शर्मनाक यह है कि वे बंगले खाली करने के बजाय तरह-तरह के बहाने बनाकर अदालतों की ओर रुख कर रहे। यह तब है जब न्यायपालिका पहले से ही बंगले खाली न करने वाले नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी जता चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन मई 2014 में हो गया था, लेकिन करीब एक साल बाद भी तमाम हारे-जीते सांसद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए रहे। ऐसे नेताओं की संख्या तीन सौ से अधिक थी। इसके चलते नए सांसदों को सरकारी खर्चे पर अन्यत्र रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें करोड़ों रुपये स्वाहा हुए। जैसे अधीर रंजन ने बंगला खाली करने से बचने के लिए नित-नए बहाने बनाए उसी तरह का काम एक समय अजित सिंह ने भी किया था। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट अधीर रंजन चौधरी को केवल डांट-फटकार लगाकर ही नहीं छोड़ता। उसे उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए था।

प्रमुखी की व्यग्रता

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के आखिरी पायदान में ब्लाक प्रमुख पद के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं। शुक्रवार को इस एक दिवसीय आयोजन में कई दावेदारों और उनके हमदर्दों ने हद से आगे जाकर पद व्यग्रता प्रदर्शित की और व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आए। कई जगह तो दूसरा उम्मीदवार पैदा होने ही नहीं दिया गया। सेटिंग-गेटिंग और समझौते-धमकाने का दौर तो चला ही, विरोधी उम्मीदवार के नामांकन पत्र तक फाड़ डाले गए। बहरहाल, नामांकन भरे जाने के दौरान जो भी हुआ वह पद लोलुपता की ओर इशारा करता है। यह भी कहता है कि कुछ तो खास है इस पद के साथ, तभी सत्ता पक्ष से लेकर महत्वाकांक्षी राजनेता तक कोई भी इसे गंवाना नहीं चाहता। फंड के लिहाज से देखें तो ब्लाक प्रमुख के पास विकास योजनाओं के लिए सालाना एक करोड़ रुपये का बजट है, साथ ही ब्लाक में आने वाली अन्य योजनाएं भी उसकी मेज से होकर गुजरती हैं। क्षेत्र में रुतबा होता है। अपना सरकारी आफिस और साथ चलने के लिए बीडीसी के रूप में कई जनप्रतिनिधि। इस दौर में यह उनके लिए ज्यादा मुफीद दिखाई दे रहा है, जिनके करीबी राजनीति में कोई मुकाम हासिल कर चुके हैं और क्षेत्र में उनका दबदबा भी है।

लोकतंत्र तो नियम-कानून और अपने कर्तव्यों के निर्वहन से ही चलता है। तभी कहा जाता है कि सत्ता हस्तांतरण का सबसे खूबसूरत तरीका इसी प्रणाली के पास है जिसमें कुर्सी पर बैठा व्यक्ति बिना किसी शोर-शराबे के खुद ही सत्ता त्याग देता है। लेकिन, प्रदेश के कोने-कोने से सामने आए चंद उदाहरणों ने तो भविष्य के लिए चिंता पैदा कर दी है। सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्यों न इसका तरीका ही बदल दिया जाए, क्यों न ब्लाक प्रमुख का चुनाव परोक्ष के बजाय प्रत्यक्ष मतदान के जरिये कराया जाए। जनता जिस भी समाजसेवी, राजनेता, युवा, अनुभवी को इस कुर्सी पर बिठाना चाहेगी, उसके लिए वह सीधे ही वोट करे, सदस्यों के जरिये नहीं। इतना तो किया ही जाना चाहिए कि हर राजनीतिक दल इसमें खुलकर भाग ले और अपने झंडे पर चुनाव लड़े। इससे चुनाव में दलीय अनुशासन तो होगा ही, वोट देने वाले सदस्यों का शोषण भी रुकेगा, लगभग बंधक जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। राजनीतिक दलों में भी संगठनात्मक उदासी टूटेगी, कार्यकर्ता का मनोबल उठेगा और अपना लोकतंत्र मजबूत होगा।

अनुपम खेर की व्यथा कथा

पाकिस्तानी वीजा न मिलने से आहत-आक्रोशित अभिनेता को संयम बरतने की सलाह दे रही हैं मृणाल पाण्डे

कश्मीर घाटी से पंडितों के जबरिया निष्कासन का इतिहास जिन लोगों ने एकदम करीब से देखा और भुगता है, उनमें से एक हिंदी के जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर हैं। पत्नी किरण खेर के सांसद चुने जाने के बाद से वह लगातार केंद्र सरकार की आलोचना करने वालों पर जवाबी कार्रवाई की स्क्रिप्ट लिए भाजपा के ग्रीन रूम में मौजूद रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में गोकशी को लेकर एक व्यक्ति की हत्या पर असहिष्णुता का मुद्दा उठा और वरिष्ठ लेखकों, कलाकारों द्वारा सरकारी सम्मानों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने कई बार इस सिलसिले का विरोध ही नहीं किया, बल्कि खुद भी टीवी के पर्दे पर आकर सम्मान वापस करने वालों पर निजी आरोप जड़ते हुए धारदार शाब्दिक हथियार चलाए।

शायद वह लेखक होते तो घाटी के पंडित पलायन का अच्छा खासा इतिहास भी लिख सकते थे। संभवतः बॉलीवुड के लाभकारी धंधे से इतनी लंबी छुट्टी लेना सेफ न होता हो। लिहाजा उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों, खासकर पाकिस्तान प्रेरित आतंकियों के ढाये जुल्मों और उनकी विवशता तथा शरणार्थी जीवन की जिल्लतों पर हाल में एक लंबा-सा आत्मकथ्य डॉक्युमेंटरी के रूप में जारी किया। इसे बार-बार कई टीवी चैनलों पर चलाया गया। पाकिस्तान और घाटी के अलगाववादी धड़ों के बीच उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया होनी ही थी, सो हुई। इसके बाद पांच फरवरी से कराची में होने जा रहे एक साहित्य उत्सव में भारत से न्योते गए 18 लोगों की फेहरिस्त में पाक विदेश विभाग ने महज उनका ही नाम वीजा योग्य लोगों की फेहरिस्त से हटवा दिया। इस पर शायद बहुत अचंभा किसी को न हुआ होगा। खुद अनुपम खेर ने कई दर्जन ट्वीट कर जाहिर किया कि उनको इससे बहुत ठेस पहुंची। आनन-फानन एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने यह भी बताया कि उनको वीजा महज इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि वह कश्मीरी पंडित हैं और घाटी से पाकिस्तान परस्त हुकूमत द्वारा जबरन दर-बदर किए गए हिंदुओं के हक में आवाज उठाते रहे हैं। वह कश्मीर के लोगों को बांट नहीं रहे और न ही कश्मीरी पंडित होने का कार्ड खेल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान यात्रा के लिए तीसरी बार उनका वीजा ठुकराया गया। कराची के साहित्योत्सव आयोजकों ने भी साफ किया कि उन्होंने अनुपम खेर को बुलाया जरूर था, लेकिन उनको सरकार की तरफ से सलाह मिली कि वह उनके आने की उम्मीद न करें, क्योंकि उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। जैसी जानकारों को उम्मीद थी, भारत में पाकिस्तान उच्चायोग ने बड़े ठंडेपन से उनका दावा खारिज कर दिया। हालांकि उनकी प्रेस कांफ्रेंस के बाद पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने उन्हें वीजा आवेदन देने की बात कही, लेकिन उन्होंने धन्यवाद सहित मना कर दिया।

पाकिस्तानी उच्चायोग के अनुसार अनुपम खेर की तरफ से सिर्फ उनके सेक्रेटरी का फोन आया था। खुद उनकी तरफ से पाकिस्तानी वीजा पाने के लिए कोई अपेक्षित औपचारिक आवेदन उच्चायोग को नहीं दिया गया था। ऐसे में उनको वीजा देने का सवाल ही कहां उठता है? लगता है, अपनी तमाम अभिनय क्षमता के बावजूद अनुपम खेर भारत पाक के जटिल राजनय की दुनिया में अभी नए और अनुभवहीन हैं। वह समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार की ख्याति रखने और कराची के साहित्य उत्सव की ओर से न्योते जाने के बाद भी पाकिस्तानी जनता और हुक्मरानों पर उनकी छाप मोदी भक्त और भाजपा सांसद के पति होने की ही है। जो कसर थी वह भी उनकी पंडित वापसी की जिरह वाली ताजा डॉक्युमेंटरी ने पूरी कर दी। अगर उन्हें साहित्योत्सव में जाने का मौका मिलता तो अपने ही ट्वीटानुसार वह घाटी के अन्यायपरक नस्लीय भेदभाव और महती भारतीय सहिष्णुता की विरासत पर बोलते। यह जाहिर है कि इसे लेकर पाकिस्तानी सत्ता बहुत हर्षित या उत्सुक नहीं हो सकती थी।

पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच अगर अनुपम खेर को कश्मीरी पंडितों की अविवादित बदहाली पर अपनी जायज पीड़ा सार्थक तरीके से पहुंचानी है तो जरूरी है कि वह समय रहते कुछ बुरी आदतें त्याग दें। पहली त्याज्य आदत है, टीवी पैनल चर्चाओं के दौरान उनका निरंतर सत्तापक्ष की छाया बनकर मौजूदा सरकार की हर करनी को सिर्फ ऊंची आवाज के बूते सही ठहराने और विरोधियों पर दांत पीस हमले बोलने की उतावली। पसंदीदा दल के लिए स्वामिभक्ति अपने आप में कोई ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन सच्चाई यह भी है किसी समय पर अपने सदस्यों की सारगर्भित और स्पष्ट आलोचना के बिना कोई राजनीतिक पार्टी या परिवार तरक्की नहीं करता। मोदी सरकार के सभी वे समर्थक जो पढ़े-लिखे, संवेदनशील मन-मस्तिष्क वाले अच्छे कलाकार हैं (अनुपम खेर की अभिनय कुशलता निर्विवाद है) अगर अपनी जायज आलोचना की बंदूक दूसरों के कंधों से चलाने या मीडिया कनफुसकियों की मार्फत लीक किए तथ्यों के बजाय उनको दल के भीतर-बाहर खुद अपने मुंह से कहने का जोखिम उठाएं तो पार्टी तथा उनके, दोनों के लिए अधिक अच्छा होगा। युद्ध और विपत्ति में दल के समर्थकों की सहानुभूति हमेशा अपनी सरकार से होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन युद्ध और विपत्ति में ही मित्रों द्वारा चतुर दुनियादारी या अंधभक्तिवश दिए जा रहे समर्थन से कई बार ताकतवर सरकारें भी उलट गई हैं।

आपातकालीन इंदिरा सरकार के साथ और राम जन्मभूमि का ताला खोलने के बाद राजीव गांधी की सरकार का जो हश्र हुआ वह इसी कड़वी सच्चाई का गवाह है। दूसरी आदत जिससे अनुपम खेर को समय रहते छुटकारा पा लेना चाहिए, बड़बोली जिव्हा के असंयम की है। उम्र के जिस मोड़ पर वह आ चुके हैं, वहां पर उन जैसी चर्चित शख्सियत को जहां तक हो, शब्दों का वजन काफी तोल कर ही बोलना या ट्वीट करना चाहिए। तैश में आकर अपनी बेटी की उम्र की नंदिता दास को पाक प्रवक्ता कह देना तो कभी बेपनाह भोलेपन का नाट्य कर यह पूछना कि क्या मोदी की तारीफ करना राजनीतिक बात है उनको शोभा नहीं देता। वैसे भी ऐसा करना राजनीतिक बात ही है। वह एक बेहतरीन अभिनेता हैं और कई अविस्मरणीय किरदारों की रचना कर चुके हैं।

बेहतर हो अभिनेता अनुपम खेर कला पर अपना ध्यान और प्रतिभा केंद्रित करें, बंधु कलाकारों के विपरीतधर्मी विचारों को भी सहने का धीरज दिखाएं और अपने यश की कमाई ऐसी बचकानी तू-तू, मैं-मैं में न गवाएं। उनके ही ट्वीट किए शब्दों में एक शब्द जोड़ते हुए, 'हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की (राजनीतिक) फिल्म रिलीज नहीं होती।'

(लेखिका प्रसार भारती की पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

तौर-तरीका बदलें

◆ पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी अगर मीडिया और बुद्धिजीवियों के बीच अनुपम खेर को कश्मीरी पंडितों की बदहाली पर अपनी जायज पीड़ा पहुंचानी है तो जरूरी है कि वह समय रहते कुछ बुरी आदतें त्याग दें

नौकरशाही पर जरूरी सख्ती

बड़ी योजनाओं पर प्रशासनिक तंत्र की शिथिलता दूर करने के लिए नौकरशाही की निगरानी आवश्यक मान रहे हैं राजीव मिश्र

गत सप्ताह शीर्ष नौकरशाही में हुए बड़े बदलाव से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सरकारी कामकाज में शिथिलता बरतने वालों को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। 2016 के पहले महीने में ही मोदी ने दो बार विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के सचिवों के साथ कामकाज की समीक्षा की है और उन्हें फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर किसी भी तरह की कोताही को नजरअंदाज नहीं करने का स्पष्ट आदेश दिया है। संदेह नहीं कि नौकरशाहों के सशक्तीकरण के मोदी हमेशा हिमायती रहे हैं और कई बार उनके अपने मंत्रियों को भी यह नागवार सा लगा है। कई बड़े स्तंभकार मोदी के इस शासन-प्रशासन के गुजराती मॉडल को भारत के लिए नुकसानदेह मानते हैं, बावजूद इसके कि जहां गुजरात में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2005 में सिर्फ 31000 रुपये के आसपास थी वहीं वर्ष 2011 तक यह 71000 के ऊपर पहुंच गई थी। विकास के ऐसे कई मापदंड हैं जहां पर शासन-प्रशासन की 'मोदी रणनीति' गुजरात में कामयाब दिखती रही है और पूरे भारत में यह रणनीति कामयाब नहीं होगी, ऐसी सोच थोड़ी बेमानी सी लगती है। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन नौकरशाहों के हाथों में ही है और अगर इसके लिए मोदी उन पर न सिर्फ भरोसा करते हैं, बल्कि उनका सशक्तीकरण भी करते हैं तो इसमें गलत क्या है?

निःसंदेह, सवाल यहां नौकरशाहों पर भरोसा करने का नहीं है, सवाल यहां नौकरशाहों की अपने कर्तव्य परायणता और मोदी सरकार द्वारा बनाई गई नीति को बिना किसी संशय के क्रियान्वित करने का है। 'सबका साथ-सबका विकास' की रणनीति के साथ पिछले 20 महीनों में बनाई गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी से प्रधानमंत्री मोदी की निगाह टेढ़ी होती है तो यह काफी स्वाभाविक है। दूरसंचार विभाग 'कॉलड्राप' और 'नेट न्यूट्रिलिटी' जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझा नहीं पा रहा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि दूरसंचार प्राधिकरण 'डाटा सर्विसेज' के 'डिफरेंशियल प्राइसिंग (अंतर्मूल्य निर्धारण) अर्थात अलग-अलग डाटा के लिए अलग-अलग मूल्य के सिफारिशों को रद करेगा। इसका सीधा अर्थ है, फेसबुक द्वारा प्रस्तावित 'फ्री-बेसिक' या 'एयरटेल जीरो' जैसी योजनाओं पर प्रतिकूल असर। सड़क और परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय में भी ऐसे कई लोकहितकारी बड़े प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने में नौकरशाहों के सकारात्मक रुख की आवश्यकता है।

मोदी के कड़े होते रुख का प्रभावी और सीधा-सीधा असर सरकार के कार्यों पर दिखेगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री को अपने संभावित मंत्रिमंडलीय फेरबदल में भी ऐसे ही ठोस और बड़े निर्णय लेने होंगे। उन्हें अपने प्रिय मित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से कुछ सीख लेनी चाहिए। ओबामा की टीम में 15 टेक्नोक्रेट हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री एशटन बी. कार्टर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। वित्तमंत्री जैक लियू सीटी समूह के मुख्य कार्यकारी थे। आंतरिक मामलों के मंत्री शैली ज्वैल इंजीनियर थीं और बैंक व ऑयल उद्योग में कार्यरत थीं। इन तीनों में एक और समानता है, इन तीनों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। सही है कि भारत की तुलना अमेरिका से नहीं की जा सकती। ओबामा की तरह 15 टेक्नोक्रेट को अपने आसपास रखना मोदी के लिए संभव भी नहीं है। लेकिन क्या कुछ मंत्रालय जहां विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है, की कमान विशेषज्ञों को नहीं सौंपी जा सकती है? विशेषज्ञ लीक से हटकर कदम उठा सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति की राह आसान हो सकती है। नौकरशाही पर पकड़ विषय के ज्ञान से ही हो सकती है। ऐसे कई मंत्रालय हैं जिसे विशेषज्ञ मजबूती से संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के कदम पहले नहीं उठाए गए हैं। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। हालांकि राव ही ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया, बल्कि सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉन मथाई को भारत का पहला रेलमंत्री बनाया था। उद्योगपति सीएच भाभा भारत के पहले वाणिज्य मंत्री बने थे।

प्रधानमंत्री कार्यालय मोदी द्वारा अपनाई गई जनहितकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर पूरी तरह प्रयत्नशील है, लेकिन उतनी ही प्रतिबद्धता कई अन्य मंत्रालयों में नहीं देखी जा रही है और ऐसे में अगर मोदी कोई विशेष निर्णय लेते हैं और कुछ विशेषज्ञों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो क्या इसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? क्या यह सही समय नहीं है? वैसे मंत्रालय या विभाग जिन्होंने पिछले 20 महीनों में कोई ज्यादा उल्लेखनीय या सराहनीय कार्य नहीं किया है उनसे बाकी के बचे 40 महीनों में क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का अहसास है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत की जनता ने उनसे काफी उम्मीद बांध रखी थी और अगले 40 महीनों में उन सारे वायदों को पूरा करना है जो उन्होने चुनाव के समय किए थे। अगर मोदी वायदा पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसमें सिर्फ उनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि सारे मुल्क के साथ-साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी होगा।

अमित शाह अभी भाजपा संगठन में बदलाव करेंगे। मोदी के पास एक अच्छा मौका है। वैसे मंत्री जिनकी मंत्रालय पर पकड़ कमजोर है, लेकिन राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं, उन्हें संगठन में 'एडजस्ट' किया जा सकता है और अगर मोदी अपने मंत्रिमंडल में मनमाफिक फेरबदल कर पाते हैं तो यह निश्चित तौर पर उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा और भारत का युवा वर्ग फिर उसी उत्साह और उमंग के साथ भविष्य की ओर देखेगा, जैसा प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के समय देख रहा था।

(लेखक बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी हैं और लोकसभा टीवी के सीईओ रह चुके हैं)

response@jagran.com

स्वाभाविक सख्ती

◆ पिछले 20 महीनों में बनाई गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर मोदी की निगाह टेढ़ी होती है तो यह काफी स्वाभाविक है

ऊर्जा

सच्चा मित्र

अपना सच्चा मित्र कौन है? विचार करें तो मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। मनुष्य के पंचभौतिक शरीर छोड़ने पर उसका धन भूमि में या तिजोरी में पड़ा रह जाता है। भवन खड़ा रह जाता है व पशु बंधे रह जाते हैं। प्यारी स्त्री शोक विह्वल भवन के दरवाजे तक साथ देती है। परिवारीजन और मित्र श्मशान तक साथ देते हैं। परलोक मार्ग में मात्र धर्म ही साथ जाता है। नीतिशास्त्र कहता है कि परदेश में मनुष्य के लिए विद्या ही मित्र है। यानी उसके पास कोई अनुभव, कला आदि है तो लोग उसका आदर करेंगे। परिवार में आज्ञाकारिणी पत्नी मित्र है।

रोग होने पर दवा मित्र का कार्य करती है और मरने वाले के लिए एकमात्र धर्म ही मित्र है। धर्म क्या है? धर्म का सार क्या है? इसका उत्तर है कि धर्म का सार सुनकर उसको धारण करना चाहिए। धर्म का सार है कि जो आचरण आपके लिए प्रतिकूल है, उसका अन्य के लिए प्रयोग न करें। दूसरों के साथ वही व्यवहार करें, जो स्वयं आप चाहते हों। यदि आप चाहते हैं कि हमारी बहन-बेटी को कोई बुरी निगाह से न देखे तो आपको भी चाहिए कि आप किसी की बहन-बेटी को बुरी निगाह से न देखें। यदि आप दूसरे का झूठ बोलना पसंद नहीं करते तो आपको भी किसी के साथ झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां धर्म है, वहीं साथ में सुख भी है। धार्मिक जीवन बिताने से आप सदा सुखी रहेंगे। कोई मनुष्य त्रिभुवन का स्वामी रहकर भी दुखी रह सकता है और दरिद्र से दरिद्र भी विश्व का सबसे सुखी प्राणी हो सकता है। प्रभु तो एक कदम और भी आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां धर्म है, वहीं पर जय है। धर्म वह प्रणाली या संस्था है, जिसकी सर्वांगपूर्ण परिभाषा बन चुकी है और जिसे 'सनातन धर्म' के नाम से पुकारा जाता है। न तो किसी समय विशेष में इसका जन्म हुआ और न किसी विशेष संस्थापक से ही इसका श्रीगणेश हुआ। यह पृथ्वीगत सीमाबंधन को नहीं मानता। जितने लोग संसार में पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे, वे सब इसी के अंतर्गत हैं। इसके नियम से मनुष्य बच नहीं सकता। हमारा धर्म सनातन है। यह त्रिपथगामी है। हमारा धर्म त्रिकर्मरत है। मानव की सभी प्रधान वृत्तियों में जो तीन वृत्तियां, ऊर्ध्वगामिनी, ब्रह्मप्राप्ति से संबंधित और बलदायिनी हैं, वे हैं सत्य, प्रेम व शक्ति। इन्हीं के द्वारा मानव-जाति की क्रमानुसार उन्नति हो रही है।

◆ डॉ. विजयप्रकाश त्रिपाठी

जागरण Junction AAPKI AWAAZ, AAPKA BLOG www.jagranjunction.com

विदेशी कंपनियों की साजिश

प्राचीन से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था कृषि व कुटीर उद्योग आधारित रही है। कृषि उत्पाद और खुदरा व्यापार की दुकानों ने ही हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। इसी के चलते हमने विश्वव्यापी मंदी से मुकाबला किया और सफल भी रहे। इस अर्थव्यवस्था से देश की आधी से अधिक आबादी जो गांवों में बसी है और बीस करोड़ की शहरी आबादी का गुजर बसर होता है। जिन बचत राशियों के आधार पर मंदी से बचने के दावे किए जा रहे हैं, वह इसी आबादी की धनराशि है। हालांकि कई विदेशी कंपनियों की नजर इस बचत राशि पर है। भारत के सोलह करोड़ परिवारों ने अगर सौ रुपये महीना भी बचाया है तो सोचा जा सकता है कि यह रकम महीने में या साल भर में कितनी होगी? कई विदेशी पूंजीपति किसान व खुदरा व्यापारी का हजारों साल पुराना रिश्ता तोड़ कर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचना चाहते हैं। इस उपभोक्ता को वह सब कुछ बेचा जाएगा, जिसकी उसे जरूरत भी न हो। जब उपभोक्ता की सारी बचत समाप्त हो जाएगी तो उसे उधार भी दिया जाएगा। **– गोपाल अग्रवाल**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1T22eMv

संपत्ति में स्त्री का अधिकार

कुछ वर्ष पूर्व तलाक के उपरांत पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार संबंधी कानून में संशोधन किया गया था। पत्नी या यूं कहें कि महिला की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। आधुनिक महिलाएं आज जब मध्ययुगीन इतिहास पढ़ती होंगी तो उन्हें यह बात चुभती होगी कि संपत्ति में भागीदारी तो दूर स्त्रियों को स्वयं ही पुरुषों की संपत्ति माना जाता था। आज भी हिंदू विवाह-संस्कार में कन्यादान की प्रथा सम्मिलित है। आयकर विधान में करदाताओं की एक श्रेणी रही है-हिंदू अविभाजित परिवार, जिसमें परिवार के ज्येष्ठ पुरुष सदस्य को कर्ता की स्थिति प्राप्त होती है। वह विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत परिवार के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसमें भी बदलाव की जरूरत है। **– जितेंद्र माथुर**

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1T23aQT

एकपक्षीय विचार

मनरेगा का मूल्यांकन शीर्षक से लिखे अपने लेख में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने संप्रग सरकार की सराहना और मौजूदा मोदी सरकार की आलोचना की है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस ने ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया था। बहरहाल जयराम रमेश को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस कानून का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए था। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा कि यह कानून कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। इसमें भारी भरकम बजट गांवों को मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऊपर से चमकती जरूर दिखाई देती होगी, लेकिन जमीन पर कोई संरचनात्मक बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। इसमें जल्द से जल्द बदलाव लाने की जरूरत है। बेहतर होता कि लेखक बताते कि आज इसमें किस तरह के सुधार किए जाएं ताकि यह सच में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सूरत बदल सके।

अनुराधा राय, रोहतक, हरियाणा

ढोंगी पाक

पाक ओर पाक सेना भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ छल कपट और ढोंग ही करती आई है। बात चाहे पठानकोट हमले या उसके जांच की या फिर सियाचिन के बर्फ में दबे सेना की मदद की हो। पाक सेना के डीजीएमओ मेजर जनरल आमिर रियाज ने सियाचिन में दबे भारतीय सेना की मदद की पेशकश की, जब पाक सेना हमारी सेना की मदद कर शांति अमन चैन और दोस्ती ही लाना चाहती है, तो फिर पाक और पाक सेना आतंकवाद को क्यों पाल पोस रहा है या उसको पनाह देता है? यह ढोंग नहीं तो और क्या है।

vikashsinghdhury@gmail.com

पाठकनामा pathaknama@nda.jagran.com

हत्या का मुकदमा

कानून में यह संशोधन आवश्यक है की यदि किसी मासूम की स्कूल कैम्पस के अंदर दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो प्रिंसिपल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि प्रिंसिपल गैर जिम्मेदार की तरह हरकत न कर सके। अभी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होने से जमानती अपराध होने के कारण प्रिंसिपल आदि मासूम की सुरक्षा से असावधान रहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छात्र दिव्यांश की मौत गैर इरादतन हत्या नहीं, यह हत्या है। ठीक उसी तरह जैसे कोई शराबी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए किसी अन्य को कुचल दे।

आमोद शास्त्री, दिल्ली

आप-भाजपा का टकराव

केंद्र की भाजपा और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच जबरदस्त टकराव से जनता बुरी तरह त्रस्त है। इससे राजधानी दिल्ली निरंतर कूड़े के ढेर में तब्दील होती जा रही है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इन बढ़ते कूड़े के ढेरों से बदबू, मच्छर-मक्खी और बीमारियों का खतरा है। दुर्भाग्य से यह टकराव अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इससे इन दोनों पार्टियों की छवि का ग्राफ तेजी से गिरता नजर आ रहा है। एक कहावत और पुरानी कहानी भी है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तो बंदर को ही लाभ होता है। इसलिए इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलकर सहयोग से सकारात्मक सोच और सही राजनीति से सेवा करने की जरूरत है वरना तो जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। दु:ख की बात तो यह है कि बिना उचित जनसेवा और सुविधा के भाजपा तो अपनी कुर्सी को सदा के लिए स्थाई करना चाहती है और दूसरी तरफ आप आदमी पार्टी भी एकदम लंबी छलांग से तुरंत इसे लेने के लिए लालायित है जोकि बिना सही और सच्ची सेवा के इतना आसान और संभव नहीं है।

वेद मामूरपुर, नरेला

स्कूलों में सुरक्षा

देश के किसी भी स्कूल में घटना होना यह अधिक दुखद और चिंताजनक बात है। हाल ही में एक स्कूल के एक मासूम बच्चे की पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। देश में स्कूलों की व्यवस्था में सुधार की काफ़ी जरूरत है। प्राइवेट स्कूल हो या फ़िर सरकारी स्कूल। यदि स्कूलों में कड़ी सुरक्षा की जाए तो किसी भी घटना से आसानी से बचा जा सकता है। हर स्तर पर हमें मासूम बच्चों के लिए अधिक देखभाल की जरूरत है। जिससे भविष्य में किसी भी तरह की घटना की गुंजाइश न रहे और देश के हर स्कूल में सुरक्षा को बढ़ाया दिया जाए।

सपना त्रिपाठी, ग्रेटर नोएड़ा

जनपथ

'चार बहादुर' सीरिया गए लड़न को धाय,
भागे तो बैठे मियां शीश कलम करवाय।
शीश कलम करवाय हाथ कुछ भी ना आया,
घर के रहे न घाट न अल्ला मिले न माया।
हुए अगर गद्दार सहोगे सबसे दुर-दुर,
जैसे शीश कटाय सह गए 'चार बहादुर'।

–ओमप्रकाश तिवारी

ट्वीट ट्वीट

यह आश्चर्य की बात है कि जिन लोगों ने कभी खेत-खलिहान नहीं देखे, किसानों की व्यथा नहीं देखी वे हम पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हैं।

- शिवराज सिंह चौहान
@ChouhanShivraj

काश शादियां चुपचाप नहीं, खुले में होतीं ताकि सब दहेज लेते-देते देख पाते और प्रथा के नाम पर गैर कानूनी काम को रोक भी पाते। ठीक कह रही हूं न?

- अल्का लांबा
@LambaAlka

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकता है?

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु में तंजानिया की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार से भारत और अफ्रीकी देशों के संबंध प्रभावित होंगे?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।